अशोका एक्सप्रेस

ASHOKA
SMA - Ashoka Express Publication

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress
E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्ष: 29 ● अंक : 11 ● नई दिल्ली ● 23 से 31 मार्च 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

आर्थिक गति बनी रही तो 2047 तक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है भारत

कश्मीरियों ने किया दिल खोलकर दान, बर्तन-नकद से लेकर महिलाओं ने सोना-चांदी भी दिया

जम्मू ।

कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में लोगों ने युद्धग्रस्त ईरान के लिए दान एकत्र किया है। इसमें नकद, सोना और तांबे के बर्तन जैसी चीजें शामिल थीं। ईरानी दूतावास ने इस मानवीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया है।

घर-घर जाकर जुटाया दान

ईद समारोह के एक दिन बाद रविवार को घाटी के शिया-बहुल क्षेत्रों में युवाओं ने घर-घर जाकर दान जुटाया। यह दान पश्चिम एशिया में ईरान पर हुए युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए था। रैनवारी निवासी ऐजाज अहमद ने इसे इस्राइल के जायोनी शासन और उसके समर्थकों द्वारा थोपा गया अवैध युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि सभ्य दुनिया को ईरान के पीड़ित लोगों को सहायता भेजनी चाहिए। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित सभी वर्गों के लोगों ने इस दान अभियान में भाग लिया।

महिलाओं ने गहने तक दिए दान

महिलाओं ने विशेष रूप से सोने के आभूषण, तांबे के बर्तन और अन्य

कीमती घरेलू सामान दान किए। कुछ परिवारों ने पशुधन भी दान किया। बच्चों ने अपनी बचत और जेब खर्च देकर योगदान दिया। यह दान मुख्य रूप से बडगाम और बारामूला में एकत्र किया गया, जहां शियाओं की अच्छी खासी आबादी है। एकत्रित योगदान को ईरानी दूतावास सहित आधिकारिक राहत संगठनों के माध्यम से जरूरतमंदों तक भेजा जाएगा।

ईरान बोला- थैंक्यू इंडिया

ईरानी दूतावास का आभार

ईरानी दूतावास ने एक्स (सोशल मीडिया मंच) पर तस्वीरों के साथ आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि कश्मीर के दयालु लोगों की मानवीय सहायता और हार्दिक एकजुटता को कभी नहीं भुलाया जाएगा। दूतावास ने यह भी कहा, हम आपकी दयालुता और मानवता को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने अपने एक अन्य पोस्ट में भारत को धन्यवाद भी दिया।

यह दान ईरान में युद्ध से हुई भारी तबाही के पीड़ितों की मदद के लिए है। युद्ध को इजरायल और उसके समर्थकों द्वारा थोपा गया बताया गया है। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों तक सीधे राहत पहुंचाना है। कश्मीर के लोगों ने इस पहल के माध्यम से अपनी एकजुटता और समर्थन प्रदर्शित किया है।

होर्मुज़ स्ट्रेट पर नरम पड़ा ईरान

यूएस- इजरायल को छोड़ दुनिया के लिए खोला रास्ता

ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई है।

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने कहा है कि यह जलमार्ग उन सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा जिनका संबंध ईरान के दुश्मनों (अमेरिका और इजरायल) से नहीं है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने 48 घंटे के भीतर रास्ता न खुलने पर ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की चेतावनी दी थी। ईरान ने स्पष्ट किया है कि अन्य देशों के जहाज तेहरान के साथ सुरक्षा तालमेल बिठाकर यहाँ से गुजर सकते हैं।

ईरानी प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई है ताकि खाड़ी क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस तनाव की असली वजह इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमले हैं। मौसवी के अनुसार, ईरान अभी भी कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन शांति के लिए बाहरी आक्रामकता का रुकना और आपसी भरोसा कायम होना बेहद जरूरी है। बता दें कि 28 फरवरी से ईरान ने इस रास्ते को बंद कर रखा था, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया है।

वैश्विक तेल सप्लाई पर मंडराता खतरा

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की कुल तेल और गैस सप्लाई के लगभग पांचवें हिस्से का मुख्य जरिया है। ईरान ने पहले संकल्प लिया था कि वह अमेरिका और इजरायल तक एक लीटर तेल भी नहीं पहुंचने देगा। इस तनाव के बीच अमेरिका ने जहाजों को सुरक्षा देने के लिए एक नौसैनिक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकांश नाटो सहयोगियों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। सहयोगी देशों का कहना है कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य टकराव का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिलहाल, ईरान के इस नए बयान से उन देशों को थोड़ी राहत मिल सकती है जो इस रास्ते पर निर्भर हैं।

केसी त्यागी रालोद में शामिल, जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता, वेस्ट की कई सीटों पर बदलेंगे समीकरण

मेरठ । वरिष्ठ राजनेता किशन चंद (केसी) त्यागी रालोद में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यकत में पार्टी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने उन्हें रालोद की सदस्यता दिलाई। नौवीं लोकसभा में हापुड़-गाजियाबाद के सांसद रह चुके केसी त्यागी पिछले 26 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) का हिस्सा थे। उनके रालोद में आने से वेस्ट यूपी की कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व रायसभा सांसद केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली जाने के निर्णय के बाद जदयू को अलविदा कहने का फैसला किया। उनका मानना है कि बिहार तक सीमित जदयू में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता के लिए भविष्य में कोई विशेष भूमिका नहीं रह जाती। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और आपातकाल के समय जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे दिग्गजों के साथ काम करने के अनुभव के साथ केसी त्यागी ने पिछले 26 वर्षों में केंद्रीय राजनीति में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उनका रालोद में शामिल होना न केवल उन्हें सक्रिय राजनीति में बनाए रखने का एक प्रयास है, बल्कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी एक और पारी खेलने का संकेत भी देता है।

इन सीटों पर पड़ सकता है असर

मोदीनगर, मुरादनगर और सिवालखास जैसी सीटों पर, जहां भाजपा के साथ गठबंधन में रालोद का दावा कई वर्तमान विधायकों और भावी प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ सकता है। यह माना जा रहा है कि केसी त्यागी इन सीटों पर अपने करीबी लोगों को टिकट दिलाने के लिए जोर लगा सकते हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ जाएगी।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

मंत्री अनिल कुमार, पूर्व मंत्री अशोक यादव, सुरेंद्र त्यागी, महासचिव त्रिलोक त्यागी, पूर्व सांसद मुंशीराम पाल, पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा, विधायक गुलाम मोहम्मद, अजय कुमार, राष्ट्रीय सचिव सुखवीर सिंह गठीना, बागपत जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर आदि मौजूद रहे।

वैंलेंटाइन डे पर दोस्ती जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में एक आरोपित की नियमित जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वैलेंटाइन-डे पर किसी लड़की का किसी लड़के से दोस्ती करना, उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं देता है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि यहां तक कि लड़की की मांग में उसकी सहमति के बिना सिंदूर लगाना भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, भले ही यह कानून में निर्धारित अपराध न हो। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने आरोपित वसीम अख्तर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने करावल नगर थाने में फरवरी 2025 में प्राथमिकी हुई थीज आरोपित के खिलाफ फरवरी 2025 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) -की धारा 64(एक) और 137(दो) और पाक्सो अधिनियम की धारा- चार के तहत प्राथमिकी की गई थी। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका विरोध करते हुए अदालत को बताया था कि 17 साल की लड़की का बयान दर्ज कराया गया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि वह आरोपित को करीब एक साल से

जानती थी। 14 फरवरी 2025 को आरोपित ने उसे बहाने से घर पर बुलाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा और उसके विरोध के बावजूद उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस घटना के बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस को सूचना दी और उसका पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया । वहीं, आरोपित के अधिवक्ता ने तक दिया कि पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा थी और उसने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे। यह भी तर्क दिया गया कि यह घटना वैलेंटाइन डे के दिन हुई थी और इससे एक प्रेम संबंध के पहलू होने का संकेत मिलता है। जबकि जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता और उसके भाई ने ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है और पीड़िता खुद जमानत का विरोध करने के लिए कोर्ट में पेश हुई थी। यह भी कहा कि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 14 जनवरी 2008 थी और उसका नाबालिग होना साबित होता है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता ने भी जमानत याचिका का विरोध किया और अदालत में मौजूद रही है। उक्त तथ्यों को देखते हुए आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी को मुकदमे के अंतिम चरण में किसी भी पक्ष के प्रतिकूल नहीं माना जाएगा।

ममता-शुभेंदु अधिकारी का रण

पश्चिम बंगाल में सबकी नज़रें कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाली लड़ाई पर टिकी हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी भाजपा की तरफ़ से चुनौती दे रहे हैं। पांच साल पहले, अधिकारी ने नंदीग्राम में बनर्जी को हरा दिया था, जिससे उन्हें अपनी पुरानी सीट भवानीपुर लौटना पड़ा था। चुनाव के तुरंत बाद शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने अपनी बॉस के लिए यह सीट खाली कर दी थी और बनर्जी ने लगभग 60,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी।

हालांकि, इस बार उनके लिए यह इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि भवानीपुर की बदलती आबादी बनर्जी के मुख्य चुनावी मुद्दे बंगाली राष्ट्रवाद से टकरा सकती है। भवानीपुर में मिली-जुली आबादी है, जिसमें से कम से कम 40 प्रतिशत लोग गैर-बंगाली हैं। ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं और इस सीट पर दुकानदार, व्यापारी और छोटे कारोबारी के तौर पर व्यापारिक केंद्र चलाते हैं।

इस तबके के बीच भाजपा का असर लगातार बढ़ रहा है। कागज़ों पर देखें तो, इस बार बनर्जी के लिए यह एक मुश्किल लड़ाई साबित हो सकती है, खासकर अधिकारी जैसे जोशीले नेता के ख़िलाफ़, जो इस सीट पर अपनी साख मज़बूत करने के लिए अपनी नंदीग्राम वाली जीत का झंडा लहरा रहे हैं। हालांकि अधिकारी नंदीग्राम से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें भवानीपुर से भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे अधिकारी बनर्जी को इसी सीट पर उलझाए रखेंगे और बंगाल के बाकी हिस्सों में उनके चुनाव प्रचार में रुकावट डालेंगे। बनर्जी टीएमसी की स्टार प्रचारक हैं और चुनाव के दौरान हर एक सीट पर जाने की कोशिश करती हैं। भाजपा की रणनीति चाहे जो भी हो, पार्टी को यह याद रखना चाहिए कि बनर्जी ने अपने राजनीतिक सफ़र में भवानीपुर से ग्यारह बार जीत हासिल की है। उन्हें इस सीट का चप्पा-चप्पा पता है और शायद हर एक वोटर का नाम भी याद है। दूसरी तरफ़, अधिकारी इस सीट के लिए बाहरी हैं। उन्हें सबसे पहले इस इलाके को समझना होगा। यह एक बेहद दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। असम में भाजपा को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के मौजूदा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि, उन्हें दिसपुर से भाजपा उम्मीदवार बनाने के फैसले को लेकर पार्टी की स्थानीय इकाई में कुछ तनाव नजर आ रहा है। इस सीट के लिए पार्टी के दावेदार अतुल बोरा नाराज हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने या कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने की धमकी दी है। किसी भी तरह से, यह भाजपा के लिए चिंता की बात है क्योंकि इससे बोरदोलोई के वोटों में सेंध लगने की संभावना है। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, बोरदोलोई को पार्टी में शामिल किए जाने से खुश नहीं हैं। यह आलाकमान का आदेश था, क्योंकि पार्टी के मुख्य चुनाव रणनीतिकार दलबदलुओं का स्वागत करके कांग्रेस को नुक्सान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सरमा के वफादार इस रणनीति से हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस से दलबदलुओं की मदद मिले या न मिले, पार्टी वैसे भी राय में जीत की मजबूत स्थिति में है। भाजपा शासित असम में कांग्रेस अपनी संभावनाओं को लेकर इतनी अनिश्चित है कि राय के लिए उसके चुनाव प्रबंधक, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सलाह के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का सहारा लिया। शिवकुमार ने हाल ही में कर्नाटक विधान परिषद की एक बैठक में यह चौंकाने वाला खुलासा किया।

उन्होंने बताया कि असम विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति (ब्लूप्रिंट) बनाने के लिए उन्होंने एक एआई प्लेटफ़ॉर्म की मदद ली थी। इसके बाद उन्होंने यह दावा भी किया कि एआई ने सुझाव दिया है कि पार्टी असम में 'कर्नाटक मॉडल' का इस्तेमाल करे। शिवकुमार ने दावा किया कि एआई ने कांग्रेस द्वारा पिछले राय चुनाव के दौरान घोषित पांच कल्याणकारी गारंटियों को असम के लिए एक सफल रणनीति माना है; इन्हीं गारंटियों की बदौलत पार्टी ने भाजपा पर शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने शासन और प्रशासनिक कार्यों के लिए एआई का इस्तेमाल करने का श्रेय अपनी बेटी को दिया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस टूल को चलाना सीखा, तो उन्हें पता चला कि यह राजनीतिक डेटा का भी विश्लेषण कर सकता है। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने असम के लिए सलाह लेने का फैसला किया। शिवकुमार और प्रियंका गांधी असम में कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की देखरेख कर रहे हैं। भाजपा ने अगस्त 2024 में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए भयानक बलात्कार और हत्या की घटना को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल को उजागर करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या पीड़ित डॉक्टर की मां को 24 परगना (उत्तर) ज़िले की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए; इसी ज़िले में पीड़ित का परिवार रहता है। यह सुझाव भाजपा के आम कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया है, वे चाहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिसने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की हो। इसके अलावा, हालांकि अब तक पीड़ित की पहचान सभी को पता चल चुकी है, लेकिन जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, तब तक उसका नाम लेना 'सब-यूडिस' (अदालती कार्यवाही के अधीन) माना जाएगा, क्योंकि कानून के अनुसार उसके नाम को गोपनीय रखना अनिवार्य है। यदि उसकी मां को चुनाव मैदान में उतारा जाता है, तो पीड़ित का नाम सार्वजनिक हो जाएगा, जिससे एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। भाजपा ने इस क्षेत्र से अपने उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। इस क्षेत्र में 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है।

सम्पादकीय

युद्ध की राजनीति और विश्व समुदाय की चुप्पी- मानवता के समक्ष एक अस्तित्वगत संकट

आज की दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है, जहाँ युद्ध और शांति के बीच का फासला निरंतर सिमटता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा, विस्तारवादी नीतियाँ और क्षेत्रीय संघर्षों ने वैश्विक व्यवस्था को गहरे अस्थिरता के भंवर में धकेल दिया है। ऐसे में यह यक्ष प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मानव सभ्यता पुनः उसी आत्मघाती मार्ग पर अग्रसर है, जिसने पिछली शताब्दी में दो भयावह विश्व-युद्धों का दंश झेला था? कोई भी संवेदनशील व्यक्ति युद्ध का समर्थक नहीं हो सकता। मानवता और प्रकृति से अनुराग रखने वाला मन भली-भाँति जानता है कि युद्ध अंततः केवल विनाश का ही पर्याय है। युद्ध की विभीषिका में सबसे पहले और सबसे अधिक आहुति निर्दोष नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की चढ़ती है। इस दृष्टि से युद्ध का विरोध करना केवल एक वैचारिक स्टैंड नहीं, बल्कि मानवता के प्रति एक सर्वोच्च नैतिक जिम्मेदारी है। विडंबना यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की यथार्थपरक धरातल अक्सर इन नैतिक मूल्यों से कोसों दूर होती है। इतिहास साक्षी है कि शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व, आर्थिक साम्राज्य और सामरिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए कमजोर देशों पर युद्ध थोपे हैं। जब-जब ऐसा हुआ है और वैश्विक समुदाय मौन रहा है, तब-तब उस चुप्पी ने अन्याय को न केवल वैधता प्रदान की है, बल्कि हमलावर को और अधिक आक्रामक होने का अवसर भी दिया है। पिछले तीन दशकों के वैश्विक मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हस्तक्षेप की यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। यूगोस्लाविया से लेकर इराक, अफ़ग़ानिस्तान, लीबिया, सीरिया और वर्तमान में यूक्रेन व सूडान तक– सैन्य हस्तक्षेपों ने समूचे भूगोल को हिंसा और असुरक्षा की स्थायी स्थिति में झोंक दिया है। लाखों का विस्थापन, हजारों निर्दोषों का संहार और सामाजिक ढांचों का पूर्ण विध्वंस इन युद्धों की वास्तविक उपलब्धि रही है। इसी पृष्ठभूमि में पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट वैश्विक नैतिकता की सबसे बड़ी परीक्षा है। फ़लस्तीन का प्रश्न पिछले सात दशकों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे संवेदनशील और अनसुलझा घाव बना हुआ है। ग़ाज़ा और पश्चिमी तट पर जारी निरंतर हिंसा ने मानवाधिकारों के दावों और अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता यह तनाव अब एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका को जन्म दे रहा है। यदि यह दावानल फैला, तो इसका प्रभाव भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे, जिससे पूरी दुनिया एक साथ प्रभावित होगी। यही वह क्षण है जब विश्व समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। क्या वैश्विक शक्तियाँ केवल अपने सामरिक हितों के चश्मे से दुनिया को देखेंगी, या वे शांति और न्याय को प्राथमिकता देंगी? यदि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं केवल शक्तिशाली देशों की राजनीतिक सुविधा का साधन बनी रहीं, तो उनकी विश्वसनीयता का अंत निश्चित है। आज परमाणु हथियारों की मौजूदगी इस संकट को कयामत के करीब ले जाती है।

बुर्क़े को लेकर यूपी वाला मॉडल बंगाल में भी लागू होगा!

गुजरात के संदेशरा बंधु का बैंकों के साथ क्लेम सेटल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के अंत में इसकी मंजूरी दी थी। संदेशरा बंधुओं नितिन और चेतन संदेशरा के साथ जांच एजेंसियों और कर्ज देने वाले बैंकों के बीच सहमति बनी थी कि 5100 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। कहा गया है कि इसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मान कर स्वीकार किया जाए और संदेशरा बंधुओं के खिलाफ बैंक घोटाले, धोखाधड़ी या लोन डिफॉल्ट सहित तमाम आपराधिक मामले समाप्त किए जाएं।

समस्या यह है कि संदेशरा बंधु की स्टर्लिंग बायोटेक पर बैंकों का बकाया 19400 करोड़ रुपए के करीब है। हैरानी की बात है कि जो डिफॉल्ट की रकम है उसके एक चौथाई के बराबर रकम को फुल एंड फाइनल मान कर सारे आपराधिक मामले समाप्त किए गए हैं। इसके मुकाबले कर्नाटक के कारोबारी विजय माल्या का मामला देखें। विजय माल्या के खिलाफ 6000 करोड़ रुपए से कुछ यादा का डिफॉल्ट था। उन्होंने बैंकों से कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। उनकी विमानन कंपनी घाटे में चल रही थी, जिससे वे समय पर कर्ज नहीं चुका सके। गिरफ्तारी के डर से वे भाग गए थे। उसके बाद से वे भगोड़ा कारोबारी हैं और सरकारी जांच एजेंसियां उनसे 14000 करोड़ रुपए से यादा वसूल चुकी है। यानी मूल रकम के दोगुने से यादा वसूली हो गई है। लेकिन ब्याज जोड़ कर रकम 20000 करोड़ पहुंचा दी गई है। एक कारोबारी का 19000 करोड़ से यादा का कर्ज 5000 करोड़ में सेटल हो रहा है और दूसरे का 6000 करोड़ का कर्ज 14000 करोड़ में भी सेटल नहीं हो पा रहा है।

यूपी वाला मॉडल बंगाल में भी लागू होगा

उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में इस मॉडल को लागू किया था लेकिन अब चुनाव आयोग ने वहां से सीख लेकर पश्चिम बंगाल में इसे लागू करने का फैसला किया है। इस मॉडल के तहत बुर्के वाली महिलाओं की जांच मतदान केंद्र के बाहर भी की जाएगी। ऐसे कह सकते है कि उनकी जांच दो बार या उससे यादा बार भी हो सकती है। आज़म ख़ान के इस्तीफ़े से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में पुलिस ने मतदान केंद्र से बहुत पहले ही बैरिकेड लगा दिए थे और बुर्के वाली महिलाओं की जांच मतदान केंद्र के बाहर ही की जा रही थी। इतनी जगह बैरिकेड लगाए गए थे और इतनी जांच हो रही थी कि बहुत से लोग रास्ते से लौट गए। बहरहाल, नियम यह कहता है कि बुर्के वाली महिला को मतदान केंद्र के भीतर जाकर ही अपना चेहरा दिखाना है। वहीं पर मतदाता सूची में लगी फोटो से उसका मिलान होगा और वोट डालने के लिए उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तय किया है कि मतदान केंद्र के बाहर ही उनकी जांच होगी। सवाल है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नया नियम क्यों बनाया गया? एक ही वजह समझ में आती है कि ऐसी जांच से बचने के लिए बहुत सी महिलाएं मतदान के लिए जाएंगी ही नहीं, जिसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होगा।

मोदी के साथ ही ऐसे संयोग' होते रहते हैं!

ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में कोई बचा या कोई व्यक्ति उनकी तस्वीर लेकर पहुंचता है और भारी भीड में भी मोदी उसे देख लेते हैं। बाद में उसे मोदी से मिलवाया जाता है। मोदी के काफिले के आगे एंबुलेंस आ जाने और उसे रास्ता दिए जाने का संयोग भी कई बार हो चुका है। हर स्थान से उनका निजी रिश्ता निकल जाना तो सबसे कॉमन संयोग है। लेकिन यह संयोग भी बहुत बार होता है कि वे रायों में चुनाव से ठीक पहले वे जिस दिन आखिरी दौरा करते हैं उसके अगले ही दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देता है। देखिए कैसा संयोग है कि प्रधानमंत्री पिछले एक महीने से तमिलनाडु, केरल, बंगाल और असम के दौरे कर रहे थे। अभी बीते 14 और 15 मार्च को उनका असम और बंगाल का दौरा होना था, लेकिन उसे एक दिन पीछे खिसका दिया गया। वे 13 और 14 को असम व बंगाल में रहे, जहां हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जम कर हमला किया। वे 14 को वहां से लौटे और 15 मार्च को चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया। यह राज तो राज ही रहेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पहले बनता है और आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में तय होती है या आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तय होती है और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम उसके हिसाब से बनता है। लेकिन संयोग दिलचस्प है।

केरल के कांग्रेस सांसदों की विधानसभा में जाने की चाह

केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को अपनी एक विचित्र अंदरुनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव की घोषणा हो गई है और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के कई सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इछा जताई है। कांग्रेस के करीब आधा दर्जन सांसद विधानसभा चुनाव टिकट चाहते हैं। वे अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने रिश्तेदार के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए टिकट चाहते हैं। असल में पिछले दो चुनाव से केरल में कांग्रेस के लगभग सभी लोकसभा उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। दूसरी ओर इस बार कांग्रेस के यादातर नेता मान रहे है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दो बार से लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा चुनाव जीत रहा है और पिनरायी विजयन मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि वाम मोर्चा हारेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसे में विधायक रहने पर राय सरकार में मंत्री बनने की संभावना रहेगी। इसीलिए कई सांसदों पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से इस बारे में बात की। हालांकि राहुल गांधी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सांसद को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाना है। सो, वेणुगोपाल कुछ नहीं कर पाएंगे।

अमृतसर में हारने वालों को बड़ा फायदा

यह कमाल का संयोग है कि पिछले 12 साल में भाजपा के टिकट पर जो भी नेता अमृतसर लोकसभा सीट से लड़ा, वह चुनाव हारा लेकिन हारने के बाद उसे बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक के बाद एक तीन नेताओं के साथ यह संयोग हुआ है। ताजा संयोग तरनजीत सिंह संधु का है, जिन्हें दिल्ली का उप रायपाल बनाया गया है। वे 2024 में अमृतसर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला से चुनाव हार गए थे। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत संधु हारने के बाद से बियाबान में भटक रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली का उपरायपाल बना कर उनका पुनर्वास किया गया है। उनसे पहले 2019 में अमृतसर से लोकसभा चुनाव हरदीप सिंह पुरी लड़े थे। उन्हें भी कांग्रेस के औजला ने हरा दिया था और उसके बावजूद पुरी केंद्र में मंत्री बने। उन्हें उत्तर प्रदेश से रायसभा में लाया गया। वे शहरी विकास मंत्री रहे और अभी एपस्टीन फाइल्स को लेकर विवादों में घिर जाने के बावजूद पेट्रोलियम मंत्री बने हुए हैं। उनसे भी पहले भाजपा के बड़े नेता अरुण जेटली भी अमृतसर में चुनाव हारे थे। उन्हें कांग्रेस के दिग्गज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हराया था। बाद में तो कैप्टन खुद ही भाजपा मे चले गए। लेकिन 2014 में अमृतसर सीट पर हारने के बाद अरुण जेटली देश के वित्त और रक्षा मंत्री बने। सो, जेटली से शुरू हुआ सिलसिला पुरी से होते हुए संधु तक जारी है।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

देहरादून में पुल के नीचे मिली ड्राइवर की लाश: जेब में सल्फास की गोली और ब्लेड मिला, 2 दिन पहले दर्ज हुई थी गुमशुदगी

देहरादून ।

देहरादून के पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र में रविवार को लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव आसन नदी के झूला पुल के नीचे पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान 32 वर्षीय महेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो पिछले दो दिनों से लापता था। परिजनों ने 20 मार्च को ही उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस को युवक की जेब से सल्फास की गोली और ब्लेड मिला है। शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम के आधार पर जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत की आशंका जताई जा रही है।

मौके से साक्ष्य जुटाए, फॉरेंसिक टीम पहुंची

रविवार दोपहर नया गांव चौकी पुलिस को सूचना मिली कि आसन नदी के पास एक शव पड़ा है। इसके बाद कोतवाली पटेलनगर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी बुलाई गई। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई।

जेब से मिला जहर और ब्लेड

पुलिस ने जब मृतक की तलाशी ली तो उसकी जेब से सल्फास की गोली और एक ब्लेड बरामद हुआ। इन सामानों के मिलने के बाद पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहरीले पदार्थ के सेवन की पुष्टि की संभावना बताई गई है।

20 मार्च से लापता था युवक

महेंद्र सिंह निवासी भूडपुर, नया गांव का रहने वाला था। वह 20 मार्च से घर से लापता था। परिजनों ने उसी दिन पटेलनगर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शव मिलने के बाद परिजनों को सूचना दी गई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर पहचान की।

काम छूटने से था परेशान, बढ़ गई थी शराब की लत

परिजनों के मुताबिक महेंद्र डंपर चलाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके पास काम नहीं था। बेरोजगारी के कारण वह मानसिक तनाव में रहने लगा था। इसी दौरान उसने शराब पीना भी बढ़ा दिया था। पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

विभागों के बंटवारे से मुख्यमंत्री पर कम हुआ भार; फिर भी 18 विभागों की जिम्मेदारी ज्यों की त्यों

देहरादून । (वेबवार्ता) कैबिनेट विस्तार से भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर विभागों का भार कम हुआ हो, लेकिन बड़े महकमों की जिम्मेदारी कम नहीं हुई है। पांच नए कैबिनेट मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होने के बाद भी मुख्यमंत्री स्वयं 18 विभागों को देखेंगे। कैबिनेट विस्तार से पहले सीएम के पास 35 विभाग थे। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों के पदों की संख्या 11 है। धामी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में आठ मंत्री थे। लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही थीं। इस बीच कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन व प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से मंत्रिमंडल में खाली पदों की संख्या पांच हो गई थी। चंदन राम दास व प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग मुख्यमंत्री के पास थे। लंबे समय से मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक की जिम्मेदारी के साथ 35 विभागों का कामकाज बेहतर ढंग से निभाया। प्रदेश के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री के कई और भी जिम्मेदारी होती है। जिस कारण विभागों की नियमित निगरानी के लिए समय कम होता है । कैबिनेट विस्तार के साथ मुख्यमंत्री अपने पास से कई विभागों को नए मंत्रियों को सौंपे हैं, लेकिन बड़े विभाग सीएम के पास ही हैं। पांच नए मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी मिलने से चुनावी वर्ष में कामकाज में तेजी आएगी। इसके साथ ही नए मंत्रियों के ऊपर भी विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन व काम में तेजी लाने की जिम्मेदारी होगी। नए मंत्रियों में खजानदास को समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से दलित वर्गों के लिए संचालित योजनाओं में तेजी लाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पहली बार मंत्री बने भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास व एमएसएमई, राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास व प्रदीप बत्रा को परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं।

गोल्डन टेंपल में बिना सिर ढके क्रिकेटर पांड्या- धोनी और कोहली भी साथ, एआई जनरेटेड तस्वीर पर विवाद

अमृतसर । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित श्री हरमंदिर साहिब (गोल्डन टेंपल) से जुड़े वीडियो और तस्वीरों का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ नई एआई जनरेटेड तस्वीरें सामने आई हैं जिससे सिख समुदाय में रोष है। वायरल हो रही तस्वीरों में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह और वर्तमान क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को श्री हरमंदिर साहिब परिसर में बिना सिर ढके खड़े दिखाया गया है, जबकि सिख धर्म में गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश करते समय सिर ढकना अनिवार्य होता है। तस्वीरों में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को भी दर्शाया गया है, लेकिन उनके सिर ढके हैं। इस भिन्नता के कारण लोगों को संदेह हो रहा है कि इन तस्वीरों को जानबूझकर इस प्रकार तैयार किया गया है, जिससे विवाद उत्पन्न हो और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था जिसमें एक कंकाल को पगड़ी पहनाकर श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा करते हुए दिखाया गया था। वीडियो में यह भी दर्शाया गया कि उक्त कंकाल जूते पहनकर लंगर हॉल में प्रवेश करता है और वहीं बैठकर लंगर ग्रहण करता है। इस पूरे मामले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने कड़ा एतराज जताया है। कमेटी का कहना है कि तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। एसजीपीसी अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट और कठोर कानून बनाए जाएं जिससे इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

डीएम सुसाइड केस- भुल्लर की गिरफ्तारी की मांग, चंडीगढ़ में सीएम आवास का घेराव, पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा

चडीगढ़ ।

अमृतसर में पंजाब वेयरहाउस कॉरपोरेशन के जिला मैनेजर (डीएम) गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या मामले सियासी तनाव बढ़ गया है। मामले में आप सरकार के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। रविवार को सभी विपक्षी दलों के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित पंजाब सीएम ऑफिस घेराव किया जा रहा है। मुख्य तौर पर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उनपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि लालजीत भुल्लर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें अब तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वह कानून से ऊपर नहीं है। मृतक गगनदीप सिंह रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर का कहना है कि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मेरे पति को बहुत प्रताड़ित किया। मेरे पति को इतना बेबस कर दिया गया कि उन्होंने अपनी जान ले ली। उन्हें कहा गया था कि उनके परिवार, उनके बच्चों को खत्म कर दिया जाएगा और उनके पीछे गैंगस्टर लगा दिए जाएंगे। 13 मार्च को उनके दफ्तर में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। शनिवार सुबह, यानी कल, उन्होंने अपनी जान ले ली। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं।

मेरी सास हैं। हम सभी न्याय की मांग करते हैं। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। रंधावा की पत्नी ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं। 13 मार्च को जब वह वापस आए, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। उन्होंने अपने विभाग में शिकायत भी की थी। वे बस उन्हें आश्वासन देते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शुरुआत में सरकार के दबाव के चलते ख्रद्धक्रदर्ज नहीं की गई थी। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि एक टेंडर पास नहीं किया गया था। यह जताया जा रहा था कि मेरे पति जान-बूझकर उसे पास नहीं कर रहे थे। मुझे अपनी जान का डर है; मुझे और मेरे बच्चों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर हमें कुछ भी होता है, तो इस सरकार की जिम्मेदारी होगी। परिवार से मुलाकात के बाद बाजवा ने कहा कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। उन्होंने पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता और अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की। बाजवा ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी जांच पंजाब पुलिस के बजाय केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और परिवार को न्याय मिल सके।

जालंधर में पुलिस और सोनू खत्री गैंग में मुठभेड़ - मुख्य गुर्गा कुलवंत गोपा गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; दो पिस्तौल और बाइक बरामद

जालंधर । जालंधर के फोल्डीवाल इलाके में पंजाब पुलिस और कुख्यात सोनू खत्री गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस क्रॉस-फायरिंग में गैंग का मुख्य गुर्गा कुलवंत सिंह गोपा, जो नवांशहर का निवासी है, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी के पास से दो पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गोपा पर फगवाड़ा की प्रसिद्ध सुधीर स्वीट शॉप पर फायरिंग करने का आरोप है और वह लंबे समय से वांछित था। उस पर पहले से ही हत्या के प्रयास और लूट जैसे 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को सोनू खत्री गैंग के गुर्गे कुलवंत सिंह गोपा की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने जब आरोपी को घेरने की कोशिश की, तो उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से करीब 10 से 12 राउंड फायर हुए। इसी दौरान एक गोली कुलवंत सिंह गोपा की टांग में जा लगी, जिसके बाद वह मोटरसाइकिल से गिर गया और

पुलिस ने उसे दबोच लिया।

फगवाड़ा गोलीकांड का मुख्य आरोपी

कुलवंत सिंह गोपा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। वह इसी साल 17 जनवरी को फगवाड़ा में सुधीर स्वीट शॉप पर हुई फायरिंग की घटना में मुख्य रूप से वांछित था। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी और तब से पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। जांच में सामने आया है कि गोपा विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के इशारे पर पंजाब में वारदातों को अंजाम देता था। वह सोनू खत्री गैंग का बेहद भरोसेमंद गुर्गा माना जाता है, जो रंगदारी और डराने-धमकाने के लिए जाना जाता है।

आरोपी के पास से दो अवैध पिस्तौल

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से दो अवैध पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गोपा कोई साधारण अपराधी नहीं है; उसके खिलाफ नवांशहर और पंजाब के अन्य जिलों में 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट और फिरौती जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। घायल अवस्था में आरोपी को इलाज के लिए नजदीकी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

इस एनकाउंटर को पंजाब पुलिस की गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस अब गोपा से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसे हथियार कहां से सप्लाई हो रहे थे और सोनू खत्री गैंग के अन्य सदस्य पंजाब में किन नए ठिकानों पर छिपे हुए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस अब गोपा के स्थानीय नेटवर्क को खंगाल रही है।

रसोई गैस महंगी और सप्लाई अनियमित, लुधियाना में विकल्पों की मांग बढ़ी, इंडक्शन और भट्टियां महंगी

लुधियाना। एलपीजी की बढ़ती कीमतों और अनियमित सप्लाई ने बाजार की दिशा में बदलाव ला दिया है। रसोई गैस की किल्लत और महंगाई से परेशान होटल, ढाबा संचालक और आम उपभोक्ता अब वैकल्पिक साधनों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। इसका सीधा असर इंडक्शन चूल्हों और गैस भट्टियों की मांग पर पड़ा है, जो अचानक कई गुना बढ़ गई है। मांग में वृद्धि के साथ ही इन उत्पादों की बाजार में कमी भी देखने को मिल रही है, जिससे इनके दाम दो से तीन गुना तक बढ़ गए हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति अचानक बनी है, जिसके चलते कंपनियां भी मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। बीके हार्डवेयर के एमडी विकास गुप्ता के अनुसार इस समय इंडक्शन चूल्हों की जबरदस्त मांग है। कई कंपनियों ने सीमित स्टाक के कारण सप्लाई घटा दी है। हर क्षेत्र से आ रही मांग के चलते उत्पादन और वितरण दोनों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कुछ नए माडल भी आए हैं, जिनमें सामान्य बर्तनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं की दिलचस्पी और बढ़ी है। हालांकि, सप्लाई में कमी का फायदा कुछ रिटेलर्स उठा रहे हैं। बाजार में इंडक्शन चूल्हों की उपलब्धता कम होने से दुकानदार मनमाने दाम वसूल रहे हैं। आम दिनों की तुलना में कीमतें दो से तीन गुना तक बढ़ चुकी हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को मजबूरी में महंगे दामों पर खरीदारी करनी पड़ रही है। पंजाब होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह के अनुसार गैस भट्टियों के दामों में भी भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की अनियमित सप्लाई

के कारण होटल संचालकों के पास विकल्प सीमित हो गए हैं। व्यवसाय को चालू रखने के लिए गैस भट्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन इनकी कीमतों में 50 से 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी ने लागत बढ़ा दी है। इस बढ़ती लागत का असर सीधे ग्राहकों पर भी पड़ रहा है।

होटलों के मेन्यू में हुए बदलाव

कई होटलों ने अपने मेन्यू में बदलाव किए हैं, जबकि कुछ ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। छोटे ढाबा संचालकों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है, जहां सीमित संसाधनों में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। व्यापारियों के लिए यह स्थिति अवसर के रूप में उभरी है, वहीं उपभोक्ताओं के लिए यह आर्थिक दबाव का कारण बन गई है। यदि एलपीजी की सप्लाई और कीमतों में जल्द स्थिरता नहीं आती तो आने वाले दिनों में बाजार में वैकल्पिक उपकरणों की मांग और कीमतें दोनों और बढ़ सकती हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मार्च को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मार्च को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके मद्देनजर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को नोएडा पहुंचे। मुख्यमंत्री दोपहर में हेलीकॉप्टर से जेवर स्थित हवाई अड्डा पहुंचे और करीब डेढ़ घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक कर उद्घाटन समारोह की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस, यमुना प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने व्यापक तौर पर तैयारियां की थीं। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हवाई मार्ग से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डा पहुंचे, जहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। इस बैठक में अधिकारियों ने समारोह की रूपरेखा, सुरक्षा योजना, जनसभा में आने वाले लोगों की संभावित संख्या और बैठने की व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा प्रबंधों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह भी गौतमबुद्ध नगर पहुंचे। उन्होंने हवाई अड्डा परिसर और जनसभा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनसभा के लिए पार्किंग व्यवस्था का सुव्यवस्थित मानचित्र तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा, प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मेघा रूपम, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) क्रिस्टोफ श्रेलमैन और सीओओ किरण जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत, 24 को पेश किया जाएगा सालाना बजट

विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक चलेगा। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि इस बार का सत्र परंपरा और तकनीक से चलेगा।

नई दिल्ली । विधानसभा का बजट सत्र 23 से 25 मार्च तक चलेगा। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि इस बार का सत्र परंपरा और तकनीक से चलेगा। 23 से 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 24 मार्च को दिल्ली का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। शनिवार को अध्यक्ष ने आठवीं विधानसभा के चौथे सत्र (बजट सत्र) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी सदस्यों से कहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखना और सार्थक चर्चा करना सबकी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष ने सदन के भीतर व्यवस्थाओं, सुरक्षा और प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया, ताकि सोमवार को कार्यवाही बिना किसी बाधा के चले। इस बार तकनीक के इस्तेमाल पर खास जोर है। सभी विधायकों की मेजों पर टैबलेट लगाए गए हैं ताकि उन्हें कार्यवाही और जरूरी दस्तावेज रियल-टाइम में मिल सकेंगे। पहली बार सदन की शुरुआत वंदे मातरम के पूर्ण गायन से होगी। इस दौरान सदन में लगी स्क्रीन पर गीत की पंक्तियां भी दिखाई जाएंगी। विधान साथी नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च हो गया है, सोमवार को विधायक इसके जरिये विधेयकों, कानून और नीतियों से जुड़ी जानकारी और विश्लेषण तुरंत ले सकेंगे। इससे विधायी कामकाज में तेजी और स्पष्टता आने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक, इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर खास ध्यान रहेगा। लैंडफिल साइटों पर जमा कूड़े को हटाने के लिए भी ज्यादा फंड रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि सरकार का बजट दिल्ली के विकास को ध्यान में रखते हुए संतुलित और समावेशी होगा।

जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से मांगा पाई-पाई का हिसाब

नई दिल्ली । देश की जेलों में कैदियों की नारकीय स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एक बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 18 मई तक अपनी जेलों का ब्यौरा पेश करें, यानी अदालत ने सभी राज्यों से पाई-पाई का हिसाब मांग लिया है। शीर्ष अदालत ने साफ-साफ कहा है कि अब पुराने आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। राज्यों को 1 मार्च 2026 तक की स्थिति के आधार पर यह बताना होगा कि उनकी जेलों में कुल कितने कैदी हैं। इतना ही नहीं, राज्यों को यह भी बताना होगा कि जेलों में कितने कैदी रह सकते हैं और अभी कितने कैदियों को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से केवल संख्या नहीं पूछी है, बल्कि यह भी पूछा है कि जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं? अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जेल-वार डेटा मांगा है। इससे यह पता चलेगा कि किस जेल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि राज्य अपनी रिपोर्ट में बताएं कि महिला कैदियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं कैसी हैं? इतना ही नहीं, कैदी मां के साथ जेल में रहने को मजबूर बच्चों के भविष्य और शिक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

अदालत का कहना है कि इन बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जेलों में बढ़ते अपराध के पीछे अक्सर सुरक्षाकर्मियों की कमी एक बड़ा कारण होती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जेल स्टाफ की संख्या और वर्तमान में खाली पड़े पदों का ब्यौरा भी मांगा है। राज्यों को यह भी बताना होगा कि इन रिक्तियों को भरने के लिए वे क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र गौरव अग्रवाल ने पीठ को बताया कि वर्तमान में शीर्ष अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े 2023 के हैं।

उन्होंने कहा कि न्याय के लिए ताजा डेटा का होना अनिवार्य है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिवों को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। बताते चलें कि अब इस मामले में 26 मई को अगली सुनवाई होगी। तब तक कोर्ट की रजिस्ट्री इन सभी हलफनामे को न्याय मित्र को सौंपेगी, जो इस डेटा का विश्लेषण कर एक विस्तृत नोट तैयार करेंगे।

कांग्रेस ने बिहार दिवस की शुभकामनाएं दीं, राहुल गांधी ने राज्य को ज्ञान-पुंज बताया

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने रविवार को बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और राहुल गांधी ने इस राय को भारत का ज्ञान-पुंज बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बिहार भारत का ज्ञान-पुंज और हमारा गौरव है- जिसने अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति से हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा, बिहार दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार को लोकतंत्र की पावन धरा और ज्ञान-परंपरा व सभ्यता का प्रतीक बताया। बिहार भारत का ज्ञान-पुंज और हमारा गौरव है - जिसने अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति से हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने एक्स पर कहा, इसी भूमि से महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध देशवासियों की आवाज को एक नयी दिशा दी थी।

पराए पानी पर जी रही राजधानी, उधारी से बुझ रही दिल्ली की प्यास; गर्मी से पहले ही पेयजल संकट

नई दिल्ली । राजधानी में एक के बाद एक करके कुएं, तालाब, झीलें सूखतीं चली गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। भूजल संचयन से कई गुना ज्यादा दोहन हो रहा है। ऐसे में धरती के पेट का पानी लगतार कम होता जा रहा है। दिल्ली कच्चे पानी के लिए सबसे ज्यादा यमुना नदी पर निर्भर है जिस पर पहले से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी और हरियाणा की प्यास बुझाने का बोझ है। स्थानीय वर्षाजल का योगदान सीमित है, जबकि भूजल का दोहन नियंत्रित स्तर पर किया जाता है। ऐसे में कच्चे पानी की मात्रा में उतार-चढ़ाव शोधन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है राजधानी के वजीराबाद और चंद्रावल संयंत्रों को यमुना से कच्चा पानी प्राप्त होता है। यमुना से मिलने वाला पानी दिल्ली के कुल पेयजल उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। गंगा का पानी अपर गंगा नहर के माध्यम से दिल्ली लाया जाता है, जिससे सोनिया विहार और भागीरथी संयंत्रों को आपूर्ति होती है। हरियाणा से आने वाली मुनक नहर और दिल्ली सब-ब्रांच नहर के जरिये भी कच्चा पानी राजधानी तक पहुंचता है। भाखड़ा स्टोरेज से मिलने वाला पानी हैदरपुर, द्वारका और नांगलोई संयंत्रों के माध्यम से शोधन के बाद वितरित किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थापित ट्यूबवेल और रैनी वेल से भूजल भी निकाला जाता है, जो कुल आपूर्ति में सहायक भूमिका निभाता है। साफ है कि दिल्ली अपने पेयजल के लिए काफी हद तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। यमुना और गंगा बेसिन से आने वाला पानी ही राजधानी की जलापूर्ति की रीढ़ है। 2024 में सीजीडब्ल्यूबी की तरफ से प्रकाशित भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन 2024 के अनुसार, दिल्ली में रिचार्ज से कई गुना अधिक पानी निकाला जा रहा है, जो भूजल संकट की तरफ इशारा करता है। दिल्ली का भूजल विकास स्तर 91 फीसदी है जो दर्शाता है कि दिल्ली का भूजल स्तर खतरे में है। 41.49 फीसदी क्षेत्र अति-दोहन की श्रेणी में है। पूर्वी दिल्ली में 98, नई दिल्ली में 135 और उत्तर पूर्वी दिल्ली 108 प्रतिशत अति-दोहन की श्रेणी में हैं, जबकि मध्य दिल्ली में 81, दक्षिण दिल्ली में 112 और दक्षिण पश्चिम दिल्ली 94 फीसदी गंभीर श्रेणी में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में अवैध बोरवेल संचालन को गंभीरता से लिया है। यह मामला वरुण लूथरा की याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि मोरया एन्क्लेव क्षेत्र में बिना अनुमति के बोरवेल से भूजल दोहन किया जा रहा है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों से जवाब मांगा था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड और अन्य अधिकारी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। एनजीटी ने इस लापरवाही पर चिंता जताई और कहा कि बोरवेल की वैधता की ठीक से जांच नहीं की गई। दिल्ली जल बोर्ड ने भरोसा दिया है कि दोबारा जांच कर सच्चाई सामने लाई जाएगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उसे धमकियां मिल रही हैं। अधिकरण ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता को सुरक्षा दी जाए। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। यमुना से मिलने वाले पानी की मात्रा पर भी मौसम प्रभाव पड़ता है। नदी में प्रवाह कम होने या हरियाणा से कम पानी छोड़ने की स्थिति में वजीराबाद और चंद्रावल संयंत्रों की क्षमता प्रभावित होती है। नहरों के माध्यम से आने वाले पानी में कमी का असर सोनिया विहार या भागीरथी संयंत्रों पर पड़ता है। दरअसल, दिल्ली का अपना कोई बड़ा जलाशय नहीं है, इसलिए भंडारण क्षमता सीमित है। ऐसे शहर रोजाना मिलने वाले कच्चे पानी पर निर्भर है। दिल्ली को दो बड़ी नदियों, यमुना और गंगा का पानी मिलता है। फिर भी, देश की राजधानी बेपानी है। इसे पेयजल से परिपूर्ण बनाने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है। बारिश का पानी बर्बाद हो जाता है। पहले जिन तालाबों, बावड़ियों, कुंओं में पानी रुकता था, आज वहां अतिक्रमण है। दिल्ली का सबसे बड़ा वाटर बैंक अरावली बेजान पड़ा है। सरकार अगर दिल्ली को पेयजल संकट से उबारना चाहती है तो स्थानीय स्रोतों पर काम करना पड़ेगा। अगर बारिश का पानी ही बचा लिया जाए तो काफी हद तक समस्या का समाधन हो जाएगा। बड़े और दिखावटी प्रोजेक्ट की जगह छोटे-छोटे, विकेंद्रित प्रोजेक्ट से पानी बचाने की कोशिश करनी होगी। गर्मियों में ही नहीं, सर्दी, बारिश में भी शहर के कई हिस्से टैंकर से पानी लेते हैं। इसकी वजह पानी की बढ़ती मांग और उत्पादन में भारी अंतर है। बढ़ती आबादी, अनियमित कॉलोनियों का विस्तार और वितरण नेटवर्क की सीमाओं के बीच उपलब्ध पानी पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि गर्मियों में मांग बढ़ने पर पानी लेने की कोशिश मारपीट, हत्या तक हो चुकी हैं।

अशोका एक्सप्रेस की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्केन करे।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र

प्रिय पाठक, विज्ञापन दात्ता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।
संपादक: विजय कुमार
Website: https://ashokaexpress.com/, Email:-ashoka.express@live.com, Mobile No. 9810674206

अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते है।
Account Holder Name : ASHOKA EXPRESS
Bank Account No. : 10650995502 & 41856402452
IFSC Code : SBIN0004846
UPI ID : 9810674206@sbi

भोजपुरी साहित्य के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर चंदेश्वर शर्मा 'परवाना' तथागत सम्मान से सम्मानित

कुशीनगर। भोजपुरी भाषा और साहित्य के प्रतिष्ठित कवि एवं साहित्यकार चंदेश्वर शर्मा 'परवाना' को 'लोक भाषा भोजपुरी व्याकरण तथागत सम्मान' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 21 मार्च, शनिवार को वाराणसी के बनारस पब्लिक स्कूल, बरजी में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिव प्रताप शुक्ला (महामहिम राज्यपाल, तेलंगाना) के करकमलों द्वारा परवाना जी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साहित्य, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन डॉ. नागेंद्र प्रसाद सिंह (पूर्व आईएएस, कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड एवं संरक्षक तथागत ट्रस्ट) के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर सदानंद शाही ने की। उल्लेखनीय है कि श्री शर्मा को इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 'राहुल सांकृत्यायन सम्मान' से सम्मानित किया जा चुका है, जो उन्हें योगी आदित्यनाथ के हाथों प्राप्त हुआ था। इस सम्मान से जनपद कुशीनगर सहित पूरे गोरखपुर मंडल के साहित्यकारों में हर्ष की लहर है। साहित्य जगत के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की है। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि भोजपुरी भाषा और उससे जुड़े हर साहित्यकार का सम्मान है। मैं आगे भी अपनी लेखनी के माध्यम से लोकभाषा की सेवा करता रहूंगा।

विश्व वानिकी दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पडरौना, कुशीनगर।

विद्यालय में प्रतियोगिता व पोखरे पर हुआ पौधारोपण

21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर एम.डी. विद्या मंदिर, दलबहादुर छपरा (निकट मिश्रौली) में विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण विषय पर आकर्षक चित्र बनाकर वृक्षों के महत्व का संदेश दिया। इसके उपरांत सभी ने पटेरा पोखरा पहुंचकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय वनाधिकारी पडरौना अशोक यादव ने कहा कि वन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और इनके संरक्षण से ही पर्यावरण का संतुलन बना रह सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण के साथ-साथ उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। वहीं जिला परियोजना अधिकारी, जिला गंगा समिति कुशीनगर नम्रता भट्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जरूरी है तथा बच्चों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जेआरएफ शुभम कुमार ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर व्यक्ति को आगे आकर पौधे लगाने होंगे, तभी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

स्थानीय रंग, पारिवारिक कहानी और बड़े कलाकार— कुशीनगर में शुरू हुई भोजपुरी फिल्म गर्भ की शूटिंग

कुशीनगर के कलाकारों को मिला बड़ा मंच, स्थानीय प्रतिभाओं को मिल रहा अभिनय का सुनहरा अवसर

कुशीनगर।

पिछले वर्ष कुशीनगर में लगातार पांच फिल्मों की शूटिंग कर चर्चा में रहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्शन अभिनेता प्रिंस सिंह राजपूत एक बार फिर जिले में अपनी नई फिल्म गर्भ की शूटिंग के लिए डेरा डाले हुए हैं। भोजपुरी माटी की खुशबू से जुड़ी यह फिल्म पूरी तरह पारिवारिक विषयवस्तु पर आधारित है, जिसकी शूटिंग जिले के विभिन्न रमणीय और ग्रामीण इलाकों में की जा रही है। फिल्म के माध्यम से स्थानीय परिवेश, संस्कृति और सामाजिक भावनाओं को बड़े पर्दे पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म गर्भ में प्रिंस सिंह राजपूत के साथ नायिका पायस पंडित और सपना चौहान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। इसके अलावा विनोद मिश्रा, बालेश्वर सिंह, हर्षित ठाकुर, देवेंद्र पाठक, राज मौर्य, राजवीर तिवारी, मनोज द्विवेदी, विजय महादेव गोस्वामी, शंभू राय, स्वीटी सिंह, गोपाल चौहान, अंशु तिवारी और शीतल गुप्ता सहित कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। स्थानीय कलाकारों में आर.के. भट्ट, डी.के. पांडेय और भुवनेश सिंह भी विभिन्न किरदारों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आईएनएन म्यूजिक और हमार टीवी चैनल के लिए बन रही इस फिल्म का निर्माण ए आर एस एम प्रोडक्शन के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता संजय सिंह और निर्देशक धनंजय तिवारी हैं। विशेष सहयोग अजय प्रताप नारायण सिंह का है, जबकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट अरविंद तिवारी और विपिन सिंह संभाल रहे हैं। फिल्म के डीओपी देवेंद्र तिवारी हैं।

स्थानीय कलाकारों को मिल रहा अवसर

इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें कुशीनगर के स्थानीय कलाकारों को भी भरपूर अवसर दिया जा रहा है। इससे न केवल क्षेत्रीय प्रतिभाओं को पहचान मिल रही है, बल्कि युवा कलाकारों को फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ने का एक सशक्त मंच भी मिल रहा है। एक बार फिर कुशीनगर की धरती पर फिल्मांकन से स्थानीय कलाकारों और दर्शकों में उत्साह का माहौल है, वहीं यह फिल्म क्षेत्रीय कला और संस्कृति को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

साइबर अपराध से कमाई 31 लाख की संपत्ति कुर्क, अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल बनाकर कमाता था मुनाफा

थाना महुआडीह पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की कार्रवाई, आरोपी तेज नारायण सिंह पहले ही हो चुका है गिरफ्तार

देवरिया। साइबर अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई में जिला पुलिस को एक और सफलता मिली है।

थाना महुआडीह पुलिस ने रविवार को न्यायालय के आदेश पर एक आरोपी द्वारा अपराध से अर्जित अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई धारा 107(4) बीएनएसएस के तहत की गई। आरोपी तेज नारायण सिंह पुत्र हंसनाथ सिंह निवासी रामगुलाम टोला संकटमोचन गली, थाना कोतवाली, देवरिया को पिछले साल 3 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वह अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर फर्जी तरीके से आर्थिक लाभ कमा रहा था। उसके पास से भारी मात्रा में सिमबॉक्स, सिम कार्ड, एंटीना, लैपटॉप और राउटर बरामद हुए थे। गिरफ्तारी थाना साइबर क्राइम, एसओजी, थाना कोतवाली और बीएसएनएल कार्यालय देवरिया की संयुक्त टीम ने की थी। आरोपी के खिलाफ थाना साइबर पर मुकदमा संख्या 18/2025 धारा 318(4), 319(2), 340(2) बीएनएस, धारा 3,6 भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम 1933, धारा 42(1), 42(3)(ग)(ड़)(च) दूरसंचार अधिनियम और 66-सी, 66-डी आईटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इस मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना महुआडीह अमित कुमार राय कर रहे हैं। विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी ने अपराध से अर्जित धन से अचल संपत्ति खरीदी है। इसके बाद न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर वाद संख्या 309/2026 धारा 107(4) बीएनएसएस के तहत आरोपी द्वारा अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्ति में आराजी संख्या 735 और 736 के तहत आने वाली जमीन शामिल है। कुल 0.007.71/100 हेक्टेयर जमीन को कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 31, 31, 680 रुपये बताई गई है। यह संपत्ति आरोपी की पत्नी पुष्पा देवी और बहू रिम्पा सिंह के नाम पर दर्ज थी। कुर्की की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी महुआडीह अमित कुमार राय के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिग्विजय सिंह, हेड मोहर्रिर ओमप्रकाश यादव, कांस्टेबल दीपक कुमार, कांस्टेबल प्रमोद गौड़, महिला आरक्षी रीता चौहान, महिला आरक्षी रिंकी यादव के अलावा थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक वरुण सिंह, उपनिरीक्षक रिद्धन सिंह, मुख्य आरक्षी मृत्युंजय कुमार और कांस्टेबल रोहित सरोज शामिल रहे।

भुजौली खुर्द में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर- 326 मरीजों को मिला उपचार, पवन दूबे की पहल बनी मिसाल

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

विकास खण्ड खड्डा के ग्रामसभा भुजौली खुर्द में रविवार को समाजसेवी एवं शिक्षाविद् पवन दूबे के नेतृत्व में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर ने मानव सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की। गोरखपुर के आस्था मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. डी.के. सिंह एवं उनकी टीम ने मरीजों का सूक्ष्म परीक्षण कर निःशुल्क परामर्श और दवाएं वितरित कीं। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय वर्मा की उपस्थिति से शिविर और भी प्रभावी रहा। कुल 326 मरीजों ने पंजीकरण कराकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। इस आयोजन की खास बात पवन दूबे की सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित किया कि किसी भी जरूरतमंद को कोई असुविधा न हो। आगंतुकों के लिए जलपान की व्यवस्था भी उनके द्वारा ही कराई गई, जो उनके सेवा भाव को दर्शाती है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्वास्थ्य शिविर किसी वरदान से कम नहीं हैं, जहां अब भी बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच सीमित है। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रामसभा के गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विपिन मल्ल, अशोक तिवारी, इरफान अंसारी, सचिन, जगजीवन, श्रवण, रियाजुद्दीन, पिंटू, शमसुद्दीन, सुमन देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। यह शिविर केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा और सहयोग पहुंचाने की सोच का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया।

ईरान से पाबंदी हटने पर भारत का कम हो सकता है तेल संकट, अमेरिका ने लिया प्रतिबंध पर यू-टर्न

नई दिल्ली । अमेरिका द्वारा ईरान के तेल निर्यात पर पाबंदी हटाने के ऐलान से वैश्विक तेल संकट कम करने में मदद मिल सकती है। भले ही यह सीमित वक्त के लिए हो, लेकिन मुश्किल हालात में इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों को कम करने में मदद मिलेगी। भारत को भी अपने ऊर्जा संकट से निपटने में इस फैसले कुछ राहत मिल सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत की तेल रिफाइनरियों के पास कच्चे तेल को प्रोसेस करने की उच्च तकनीक व लॉजिस्टिक क्षमता है और वे काफी समय से रूसी तेल को प्रोसेस करने में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

हाल में अमेरिका ने कुछ वक्त के लिए ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की बात कही है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय अभी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि अमेरिका की ओर से खरीद शर्तें अभी स्पष्ट होनी हैं। इसके बाद भारत की तेल रिफाइनारियां खरीद का निर्णय करेंगी। इस वक्त ईरान का 140 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल समुद्र में जहाजों पर ही है। इसका बड़ा हिस्सा चीन जाना है। पर बड़ी मात्रा अभी बिक्री के लिए है। इसे भारत ही नहीं तेल संकट से गुजर रहे अन्य देश लेने की कोशिश में हैं। पर भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। इस्त्राइल- अमेरिका से युद्धरत ईरान भी भारत से कई तरह का समर्थन चाहता है। इसीलिए उसने स्ट्रेट आफ होर्मुज से भारतीय ऑयल टैंकर को गुजरने की अनुमति दे रखी है। इस समय कच्चे तेल के दाम 156 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए हैं। भारत अभी ऊर्जा का 85 प्रतिशत विभिन्न देशों से आयात करता है। वर्ष 2018-19 में भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 10.6 प्रतिशत होती थी। जब 2019 में अमेरिका ने ईरान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए तो उसके बाद से भारत का आयात कम होता चला गया और अब मामूली व्यापार रह गया है। साल 2025 में ईरान से महज 0.44 बिलियन डॉलर का आयात किया गया। जबकि 1.24 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना में बदलाव, मशीनरी की लागत पर अब 75 नहीं 60फीसदी का कैप

नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना में बदलाव का एलान किया है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए है। यह संशोधन विनिर्माताओं और निर्यातकों को समर्थन देने के उद्देश्य से किया गया है। संशोधित योजना में चौथे वर्ष के बाद किस्तों में पांच फीसदी अग्रिम योगदान की अनुमति है। एनसीजीटीसी ने 24 फरवरी, 2026 से इस योजना को लागू कर दिया है। संशोधित योजना में सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। उपकरण या मशीनरी की लागत को परियोजना लागत के 75 फीसदी से घटाया गया है। अब यह 60 फीसदी कर दी गई है। पहले यह सीमा 75 फीसदी थी। नई योजना के अनुसार, ऋण गारंटी 10 साल बाद समाप्त हो जाएगी। पुरानी योजना में इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। योजना का उद्देश्य एमएसएमई को संयंत्र और मशीनरी/उपकरण खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। इससे भारत के विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सहायक होगा। इस योजना का लाभ उन लाभदायक इकाइयों को मिलेगा। जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपने बिक्री कारोबार का कम से कम 25 फीसदी निर्यात किया है। उन्हें कुछ निर्यात प्राप्ति शर्तों को भी पूरा करना होगा। गारंटीकृत ऋण राशि 20 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। अग्रिम योगदान ऋण राशि का दो फीसदी होगा। यह अधिकतम 40 लाख रुपये तक हो सकता है। गारंटी अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष में एक-एक फीसदी राशि वापसी योग्य होगी। गारंटी कवरेज चूक की राशि का 75

फीसदी होगा। पहले वर्ष के लिए गारंटी शुल्क शून्य रहेगा। उसके बाद हर साल बकाया ऋण का 0.50 फीसदी शुल्क लिया जाएगा। यह योजना जनवरी 2025 में शुरू की गई थी। इसके तहत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को ऋण सुविधाएं मिलती हैं। 100 करोड़ रुपये तक की इन सुविधाओं के लिए गारंटी कवरेज मिलता है। यह कवरेज 60 फीसदी तक प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 फीसदी का योगदान करते हैं। ये देश के कुल निर्यात में 45 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। एमएसएमई 35 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। इन संशोधनों से निर्यातक एमएसएमई सहित सभी एमएसएमई के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ेगी। यह क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सोमवार को ये शेयर रहेंगे फोकस में

नई दिल्ली । मिडिल ईस्ट तनाव का असर भारतीय बाजार समेत वैश्विक बाजारों में भी देखने को मिल रहा है. बीते सप्ताह भी घरेलू शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा. हालांकि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. अनिश्चितता भरे माहौल के बीच अब निवेशकों की नजर कल यानी 23 मार्च के ट्रेडिंग डे पर होगी. इस दिन कुछ शेयरों में हलचल की उम्मीद की जा रही है. साउथ इंडियन बैंक में मैनेजमेंट स्तर पर अहम बदलाव किए गए है. मौजूदा चेयरमैन वी जे कुरियन के रिटायर होने की खबर सामने आ रही है. उनकी जगह जोसे जोसेफ कट्टूर नए चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे. यह बदलाव 23 मार्च 2026 से प्रभावी होगा. जोसेफ कट्टूर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है. इस खबर के आने के बाद सोमवार को कंपनी शेयर निवेशकों के रडार पर रह सकते हैं. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हाल ही में बड़े ऑर्डर मिलने के बाद इसके शेयर पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है. कंपनी को प्रसार भारती की ओर से करीब 1,598 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है.जिसके तहत क्लाउड बेस्ड न्यूज रूम तैयार किया जाएगा और इसे 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है. इसके अलावा कंपनी को भारतीय रेलवे से करीब 24 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर भी मिला है. जिससे इसका ऑर्डर बुक मजबूत हुआ है. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए 3.25 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है. इस डिविडेंड के लिए 23 मार्च को रिकॉर्ड डेट तय की गई है. जिसके आधार पर पात्र शेयरधारकों को इसका लाभ मिलेगा.

सोमवार को टाटा कैपिटल के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. इसके पीछे की वजह की बात करें तो, कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करीब 413 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है. हालांकि, कंपनी ने इसे पूरी तरह से गलत बताया है. कंपनी का कहना है कि, इस मामले में वे अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे. कंपनी का मानना है कि, यह फैसला उनके पक्ष में ही आएगा. ऐसे में कंपनी शेयर निवेशकों की रडार पर हो सकते हैं.

पश्चिम एशिया संकट व कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सुस्त बाजार की चाल

मुंबई। भारतीय इक्विटी मार्केट में यह सप्ताह बहुत अधिक उतार-चढ़ाव वाला रहा, लेकिन स्थिर रहा, जिसमें पिछले हफ़्ते के तेज करेक्शन के बाद सेंटिमेंट में शॉर्ट-टर्म राहत के संकेत दिखे। जबकि पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ था, कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी ने और गिरावट को रोकने में मदद की, जिससे इंडेक्स ज़रूरी सपोर्ट ज़ोन के पास मज़बूत हो सके। हालांकि, इस हफ्ते ज्यादातर दिन के दौरान तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिले, जो चल रहे जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव की वजह से हुआ। बाजार विशेषज्ञों का कहना है बाजार नए सप्ताह में रक्षात्मक और थोड़ी सुस्त चाल के साथ शुरुआत करने की संभावना है। निवेशक सावधानी के साथ कारोबार करेंगे। क्योंकि मार्केट की दिशा ग्लोबल डेवलपमेंट विशेषकर कच्चे तेल के रुझानों और भू-राजनीतिक स्थितरता पर अधिक निर्भर करती है।

नया सप्ताह रक्षात्मक और थोड़ी सुस्त चाल के साथ शुरू होने की संभावना

लाइवलॉन्ग वेल्थ के संस्थापक और रिसर्च एनालिस्ट हरिप्रसाद कहते हैं, भारतीय इक्विटी आने वाले हफ्ते की शुरुआत सावधानी के साथ करने वाले हैं, गिफ्ट निफ्टी से शुरुआती संकेतों से गैप-डाउन ओपनिंग का संकेत मिल रहा है। निफ्टी स्पॉट पर 300 पॉइंट्स का बड़ा डिस्काउंट बताता है कि सेंटिमेंट अभी भी कमजोर बना हुआ है, और जब तक कोई अच्छा ट्रिगर सपोर्ट नहीं करता, आने वाले हफ़्ते की शुरुआत में गिरावट का रिस्क ह्वी हो सकता है। बाजार नए सप्ताह में रक्षात्मक और थोड़ी सुस्त चाल के साथ शुरुआत करने की संभावना है।

जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी जारी रहने की पूरी उम्मीद है, जो लगातार विदेशी संस्थाग निवेशकों की बिक्री को संतुलित करती दिखाई दे सकती है।

एफआईआई की बिकवाली, कमजोर वैश्विक संकेत, कमोडिटी की बढ़ी हुई कीमतें और सतर्क डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग सीमित अपसाइड पोटेंशियल का संकेत देते हैं। वे कहते हैं, बड़ी स्ट्रक्चर से पता चलता है कि रैलियों में बिकवाली जारी रह सकती है, मार्केट की दिशा वैश्विक घटनाक्रम विशेषकर कच्चे तेल के रुझानों और भू-राजनीतिक स्थितरता पर अधिक निर्भर करती है।

कच्चे तेल की कीमतें, करेंसी में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना

जियोजित इंवेस्टमेंट लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर कहते हैं, आगामी हफ्ते में बाजार में भू-राजनीतिक डेवलपमेंट, कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी में उतार-चढ़ाव जैसी सेंसिटिव बनी रहने की संभावना है।

शॉर्ट-टर्म कैटलिस्ट में जापान और यूके से महंगाई के आंकड़े, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की जेरोम पॉवेल की कमेंट्री और भारत व अमेरिका के पीएमआई डेटा आने पर नजर रखी जाएगी। हालांकि भू-राजनीतिक जोखिम और मैक्रोइकोनॉमिक मुश्किलों से होने वाली शॉर्ट टर्म वोलैटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन चल रहे करेक्शन और वैल्यूएशन रीसेट से धीरे-धीरे निवेशक लॉंग टर्म में निवेश करने के तरिकों को अपना सकते हैं।

बाजार की हालिया दिशा कच्चे तेल और भू-राजनीतिक घटनाक्रम से होगी तय

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी कहते हैं, आगामी बाजार की दिशा अल्पावधि में काफी हद तक पश्चिम एशिया के घटनाक्रम, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बदलते हालात पर निर्भर करेगी। कोई भी लंबे समय तक रुकावट कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ला सकती हैं, जिससे महंगाई और करंट अकाउंट का दबाव बढ़ सकता है, जबकि रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट बना रहेगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार निकासी और वैश्विक संकेत सहित डॉलर की मजबूती और अन्य बड़े बाजार की चाल भी शेयर बाजार को प्रभावित कर सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी एक शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू कर सकती है, जबकि कीमतों में तेज वृद्धि बाजार में दबाव बना सकती है।

20 महीने का एरियर जोड़ मिलेगी मोटी रकम, 15 लाख तक का आएगा खर्च!

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरो पर हैं. लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है. रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी फिलहाल सुझाव ले रही है. इस पर 2026 के अंत या 2027 तक फैसला आ सकता है. इसके बाद ही तय हो पाएगी कि सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. ऐसा माना जा रहा है कि अगर आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू माना जा रहा है, लेकिन इसे देने में 20 महीने तक की देरी हो रही है तो सरकार पूरे 20 महीने के एरियर को जोड़कर यह रकम देगी. इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का 20 महीने का एरियर 3.6 लाख रुपये से लेकर 15 लाख के बीच बैठेगा. यह उनके बेसिक पे पर निर्भर करेगा. फिटमेंट फैक्टर वह नंबर है जिसका इस्तेमाल पे कमीशन के तहत बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए किया जाता है. 7वें पे

कमीशन में इसे 2.57 पर सेट किया गया था, जिससे सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी. आने वाले 8वें पे कमीशन के लिए कर्मचारी यूनियन 3.0 से 3.25 के ज्यादा के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि इसकी जरूरत है क्योंकि पिछले 10 सालों में महंगाई और रहने का खर्च बहुत बढ़ गया है. ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का मतलब है बेसिक सैलरी, पेंशन और कुल इनकम में ज्यादा बढ़ोतरी. कम और मिडियम रेंज की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है जैसे कि लेवल 1 के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 है, तो मल्टीप्लायर के आधार पर यह बढ़कर लगभग 36000 से 46260 रुपये तक हो सकती है. इसी तरह लेवल 6 के किसी कर्मचारी की सैलरी अगर अभी 35400 रुपये है, तो यह बढ़कर 70800-90978 रुपये तक हो सकती है. लेवल 8 के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 47600 है, तो 2.57 के फैक्टर पर यह 1.2 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है और अगर 3.0+ का फैक्टर मंजूर होता है, तो यह और भी ज्यादा हो सकती है. कुल मिलाकर मासिक सैलरी में बढ़ोतरी 18000 से लेकर 74000 रुपये से भी ज्यादा तक हो सकती है. बकाया राशि या एरियर आठवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले सबसे बड़े वित्तीय लाभों में से एक होने की उम्मीद है. चूंकि नई वेतन संरचना 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकती है इसलिए कर्मचारियों को 18-24 महीनों का बकाया मिल सकता है.

अनुमानित बकाया राशि निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए लगभग 3.6 लाख से लेकर उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए 14-15 लाख तक हो सकती है. इससे एक बड़ा

क्या बांग्लादेश के साथ हो सकती है भारत की सीरीज? बीसीबी ने अचानक क्यों स्थगित किया आयरलैंड दौरा

ढाका । बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने सितंबर 2026 में होने वाला आयरलैंड दौरा स्थगित कर दिया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, बोर्ड इस अवधि के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक, जब भारत के साथ होने वाली सीरीज को 2025 से शिफ्ट कर सितंबर 2026 में किया गया था, उसी समय क्रिकेट आयरलैंड से नई तारीख देने का अनुरोध किया गया था। तब आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2026 में दौरे को आगे बढ़ाने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद दोनों बोर्ड आपसी सहमति से सीरीज को टालने पर सहमत हुए। बांग्लादेश का आयरलैंड दौरा 2027 में किसी समय आयोजित किया जा सकता है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम तीन वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज के लिए 28 अगस्त 2026 को बांग्लादेश पहुंच सकती है। वनडे मुकाबले एक, तीन और छह सितंबर को, जबकि टी20 मैच नौ, 12 और 13 सितंबर को खेले जा सकते हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को अपने घर में वनडे सीरीज में 2-1 से हराया है। सीरीज जीतने के बाद बांग्लादेश आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नौवें स्थान पर पहुंच गया है। टीम के 79 रेटिंग प्वाइंट हैं और वह 10वें स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज से आगे है। बांग्लादेश का ध्यान वनडे विश्व कप 2027 के लिए क्वालिफाई करने पर है। विश्व कप में सीधे क्वालिफाई करने के लिए बांग्लादेश को 31 मार्च 2027 तक टॉप-8 में जगह बनानी होगी। अगर टीम ऐसा नहीं कर पाती तो उसे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। आयरलैंड दौरे के टलने के बाद बांग्लादेश के पास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे का कार्यक्रम है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में असामान्य रहे हैं। बांग्लादेश टी20 विश्व कप 2026 के मैच खेलने के लिए भारत नहीं आई थी और विश्व कप का बहिष्कार किया था। ऐसे में भारतीय टीम वनडे और टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी या नहीं, इस पर फिलहाल निश्चितता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर भारत का दौरा किसी कारण से टलता है तो बांग्लादेश के पास क्वालिफिकेशन डेडलाइन से पहले सीमित वनडे मैच ही बचेंगे, जो सीधे विश्व कप में उसकी एंट्री को मुश्किल बना सकते हैं।

लगातार दो हार के बाद दक्षिण अफ्रीका का पलटवार, न्यूजीलैंड से सीरीज की बराबर, क्राइस्टचर्च में होगी निर्णायक जंग

वेलिंगटन। दक्षिण अफ्रीका ने वेलिंगटन में खेले गए चौथे टी20 में न्यूजीलैंड को 19 रन से हराकर सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है. 165 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी न्यूजीलैंड 145 रन पर ही सिमट गई. न्यूजीलैंड को ये मैच और सीरीज जीतने के लिए 165 रन की जरूरत थी. कीवी टीम की बल्लेबाजी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी की सामने लड़खड़ाई गई और 18.5 ओवर में 145 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज टिम रॉबिनसन ने सर्वाधिक 32 रन की पारी खेली. डेन क्लीवर ने 26 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका. दक्षिण अफ्रीका के लिए गेराल्ट कोएट्जी ने 3, ओटेनिल बार्टमैन, पी सुब्रायन और केशव महाराज ने 2-2, और वियान मुल्डर ने 1 विकेट लिए. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 164 रन बनाए थे. विकेटकीपर बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन ने सर्वाधिक 57 रन की पारी खेली. 36 गेंदों की इस पारी में एस्टरहुइजन ने 3 छक्के और 7 चौके लगाए. इसके अलावा टोनी डे जॉर्जी ने 23, रुबिन हर्मनन ने 28, डियान फोरेस्टर ने 19 और जेसन स्मिथ ने 19 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए काइल जैमिसन ने 2, जकारी फॉक्स, बेंजामिन सियर्स और कोले मोकोंची ने 1-1 विकेट लिए. सीरीज 2-2 से बराबर हो चुकी है. पांचवां और निर्णायक मुकाबला 25 मार्च को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के साथ ही महिला टीम भी 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर है. साउथ अफ्रीका की महिला टीम को टी20 सीरीज गंवानी पड़ी है. न्यूजीलैंड ने सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है. महिला टीम का भी पांचवां और आखिरी मुकाबला 25 मार्च को क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप 2026 नजदीक है.

इसलिए महिला क्रिकेट टीम में इन दिनों टी20 की धूम है. ऑस्ट्रेलिया की टीम भी टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज दौरे पर है.

पाकिस्तान क्रिकेट का सच! गैरी कर्स्टन बोले- हारते ही कोच को बलि का बकरा बना देते हैं

नई दिल्ली । पाकिस्तान के पूर्व श्वेत-गेंद क्रिकेट के मुख्य कोच गैरी कर्स्टन ने हाल ही में टीम से अपने इस्तीफे के बारे में बात की। उन्होंने टीम के भीतर के माहौल को कठिन बताया। उन्होंने कार्य संस्कृति को विषाक्त बताते हुए टीम के भीतर सम्मान और शिष्टाचार की कमी की बात कही। यह दिलचस्प बात है कि गैरी कर्स्टन ने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के श्वेत-गेंद क्रिकेट के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल शुरू हुए महज छह महीने ही बीते थे और उन्होंने एक भी वनडे मैच नहीं खेला था। टॉकस्पोर्ट क्रिकेट को दिए एक साक्षात्कार में कर्स्टन ने कहा कि जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वह थी हस्तक्षेप का स्तर। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले कभी इस स्तर का हस्तक्षेप देखा है। क्या इसने मुझे चौंकाया? मैं नहीं जानता, लेकिन यह काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा, कर्स्टन ने बताया कि जब भी कुछ गड़बड़ होती थी, कोचिंग स्टाफ को तुरंत बलि का बकरा बना दिया जाता था। उन्होंने बताया कि लगातार बाहरी शोर-शराबे से प्रभावित होकर टीम का मार्गदर्शन करना कितना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने बोर्ड से यह भी सवाल किया कि अगर वे हर मोड़ पर कोच को ही दोष देते हैं, तो कोच की भर्ती क्यों करते हैं। कर्स्टन ने कहा कि जब बाहर से लगातार शोर-शराबा होता रहता है, तो कोच के लिए आकर खिलाड़ियों के साथ काम करने का तरीका खोजना बहुत मुश्किल होता है। यह कठिन था और खराब प्रदर्शन वगैरह को लेकर कई दंडात्मक कार्रवाई की जाती थीं। उन्होंने आगे कहा कि एक कोच के तौर पर, जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती है, तो आप सबसे आसान निशाना होते हैं, इसलिए 'चलो कोच को हटा देते हैं' या 'चलो कोच पर प्रतिबंध लगा देते हैं', क्योंकि टीम के खराब प्रदर्शन के समय यही सबसे आसान काम होता है–और मेरी राय में यह उल्टा असर डालता है।

क्या सीएसके को संजू सैमसन को बनाना चाहिए कप्तान? उथप्पा ने दिया ये जवाब; हैदराबाद के लिए कही ये बात

नई दिल्ली । भारत और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने आईपीएल 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके की कप्तानी जारी रखने का समर्थन किया है। उथप्पा का कहना है कि ऋतुराज को ही टीम की कप्तानी करनी चाहिए। उन्होंने संजू सैमसन को कप्तानी सौंपने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उथप्पा का मानना है कि इस महत्वपूर्ण बदलाव के दौर में गायकवाड़ के नेतृत्व कौशल को निखारने के लिए फ्रेंचाइजी को धैर्य रखना चाहिए।

उथप्पा बोले- धोनी की छाया से बाहर निकल रहे हैं सैमसन

उथप्पा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि सीएसके को कप्तानी की जिम्मेदारी संजू सैमसन को सौंप देनी चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान के रूप में जमने के लिए समय देना होगा। वह 2024 से टीम की कप्तानी कर रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, वह एमएस धोनी की छाया से बाहर निकल रहे हैं। आप चाहते हैं कि वह पूरी तरह से उभर कर अपनी पहचान बनाएं। आप देखना चाहते हैं कि वह क्या कर सकते हैं।

हैदराबाद को खिताब का दावेदार नहीं मानते उथप्पा

उथप्पा का मानना है कि आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खिताब की प्रबल दावेदार नहीं होगी। उथप्पा ने कहा कि भले ही हैदराबाद का बैटिंग ऑर्डर काफी दमदार नजर आ रहा हो, लेकिन टीम का गेंदबाजी अटैक काफी कमजोर दिख रहा है। उथप्पा ने कहा, सनराइजर्स हैदराबाद की आक्रामक बल्लेबाजी देखना मनोरंजक होता है। हालांकि, इस तरह की बल्लेबाजी उन्हें आईपीएल जीतने में मदद नहीं करेगी। हैदराबाद की गेंदबाजी थोड़ी कमजोर है। गेंदबाज ही होते हैं जो आपको ट्रॉफी दिलवाते हैं। हैदराबाद को अपने घरेलू मैदान पर सात मैच खेलने होते हैं, जहां की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी है। उथप्पा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास अभी ऐसा गेंदबाजी अटैक है जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से पैदा होने वाली अस्थिरता को संभाल सके, खासकर तब जब उनका टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन न करे। हम सभी ने पिछले सीजन में देखा था कि क्या हुआ था। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन के अलावा, कोई भी अन्य बल्लेबाज आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं उठा पाया था। जब टॉप ऑर्डर विफल रहा तो गेंदबाज भी उस स्कोर का बचाव करने में असमर्थ रहे। यही वजह है कि मैं इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को खिताब का एक दावेदार नहीं मानूंगा।

आईपीएल के लिए ऋषभ पंत बदल रहे रणनीति, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे लखनऊ के कप्तान

लखनऊ । लखनऊ सुपर जाएंट्स के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल 2026 में अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रहे हैं। पंत 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल के 19वें सीजन में तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। पंत इस दौरान एक बार फिर लखनऊ फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे। लखनऊ ने 2025 के लिए हुई बड़ी नीलामी में पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पिछला सीजन टीम और पंत दोनों के लिए कुछ खास नहीं रहा था।

पंत के सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा

पिछले साल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए पंत एक सफल सीजन की ओर देख रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने शीर्ष क्रम पर उतरने का फैसला किया है। ऐसा सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि इस विकेटकीपर बल्लेबाज का ध्यान भारतीय टी20 टीम में वापसी पर लगा हुआ है। पंत खेल के तीनों

प्रारूप में से केवल भारतीय टेस्ट टीम के ही अभिन्न सदस्य हैं, जबकि वनडे में वह केएल राहुल के बैकअप विकेटकीपर हैं। इस 28 वर्षीय खिलाड़ी ने 2024 में भारत की विश्व कप जीत के बाद टी20 टीम में अपनी जगह गंवा दी थी। संजू सैमसन और ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए टीम में वापसी करने के लिए उन्हें कुछ खास प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से टीम में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।

किस तरह बदलेगा लखनऊ का बल्लेबाजी संयोजन

पंत के लिए आईपीएल का आगामी सत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वह अपनी कीमत को जायज ठहराने के अलावा खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की भी कोशिश करेंगे। पंत ने पिछले सत्र में अधिकतर समय चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की थी, लेकिन तब वह आखिर के कुछ मैचों में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। उस समय तक हालांकि लखनऊ की वापसी की संभावना समाप्त हो गई थी। पंत के तीसरे नंबर पर उतरने का मतलब होगा कि निकोलस पूरन को बल्लेबाजी क्रम में नीचे आना पड़ेगा। एलएसजी की टीम अभी लखनऊ में अपने घरेलू मैदान पर अभ्यास कर रही है। उसका पहला मैच एक अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगा। मुख्य कोच जस्टिन लैंगर और उनके सहयोगी स्टाफ अपने कप्तान के बल्लेबाजी क्रम को लेकर एकमत हैं। आईपीएल सूत्रों के अनुसार, टीम प्रबंधन और पंत दोनों इस बात से सहमत हैं कि उनके लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना उपयुक्त होगा। इस साल उनके शीर्ष क्रम में एडेन मार्करम, मिचेल मार्श और पंत शामिल होंगे।

पिछले सीजन निराशाजनक रहा था स्ट्राइक रेट

पंत ने पिछले साल 133.17 के निराशाजनक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और उन्होंने केवल 269 रन बनाए जिसमें नाबाद 118 रन की एक पारी भी शामिल है। लखनऊ की टीम के मध्य क्रम में पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद और शाहबाज अहमद शामिल हैं। पिछले सत्र में लखनऊ की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गेंदबाजी रही थी क्योंकि मयंक यादव और मोहसिन खान जैसे तेज गेंदबाज चोटों के कारण उपलब्ध नहीं थे। अन्य तेज गेंदबाजी विकल्पों में आवेश खान और एनरिच नॉर्त्जे शामिल थे।

धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल: देश का पहला राज्य जहां यूसीसी लागू; सख्त नकल विरोधी कानून से 30 हजार युवाओं को मिली नौकरी

देहरादून।

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इन चार वर्षों में सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक और सख्त फैसले लिए हैं, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की एक सशक्त पहचान बनाई है। समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने से लेकर सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानून तक, धामी सरकार ने अपनी प्रशासनिक दृढ़ता का उदाहरण पेश किया है।

सख्त कानून और 30 हजार नौकरियां

युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और भर्ती घोटालों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस पारदर्शिता का ही परिणाम है कि बीते 4 वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जिससे सिस्टम पर युवाओं का भरोसा लौटा है।

महिलाओं को 30फीसदी आरक्षण

धामी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि धरातल पर उतारा। सरकारी नौकरियों में 30फीसदी क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33फीसदी आरक्षण सुनिश्चित किया गया। प्रदेश में अब तक 2.54 लाख से अधिक

महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण स्वयं सहायता समूहों को दिया जा रहा है। साथ ही, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और सशक्त बहना उत्सव योजना ने महिलाओं को आर्थिक मजबूती दी है।

सरकार ने सेवा और सम्मान के मूल मंत्र पर चलते हुए सैनिकों और राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के लिए खजाना खोल दिया।

आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया।आश्रितों की पेंशन 3000 से बढ़ाकर 5500 रुपए की गई।

7 दिन जेल गए या घायल आंदोलनकारियों की पेंशन 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रतिमाह की गई। शहीद सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर सीधे 50 लाख रुपए कर दी गई। वहीं, परमवीर चक्र विजेताओं की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए की गई। राज्य में अग्निवीरों को भी सरकारी नौकरी में 10व क्षैतिज आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया गया।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार

आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस और कैंप्स का सहारा लिया। अपुणि सरकार पोर्टल लॉंच किया। इसके माध्यम से करीब 950 सरकारी सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेशभर में 686 शिविर लगाए गए, जिनमें 5.37 लाख लोग पहुंचे। 51 हजार से ज्यादा शिकायतों में से लगभग 34 हजार का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन बढ़कर 1500 रुपए की गई (अब बुजुर्ग दंपत्ति दोनों को इसका लाभ मिल रहा है)। वहीं, कमजोर कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन 3000 से दोगुनी कर 6000 रुपए कर दी गई है।

बच्चों में टीबी की पहचान और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयोजित किया गया टीबी जांच स्वास्थ्य शिविर

***स्वास्थ्य शिविर के दौरान जिला में हुई 100 दिवसीय निक्षय अभियान की शुरूआत**

***बच्चों में टीबी पहचान के लिए समय पर जांच और जागरूकता अत्यंत आवश्यक-डिप्टी सीएमओ डॉ. तरूण यादव**

सोनीपत।

इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) व जिला टीबी कार्यालय के सहयोग से रविवार को बच्चों में तपेदिक(टीबी) की शीघ्र पहचान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशाल मेगा पीडियाट्रिक टीबी डिटेक्शन एवं चाइल्ड हेल्थ केयर कैंप का सफल आयोजन किया गया। यह स्वास्थ्य शिविर वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एन.के. मित्तल के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों और अभिभावकों ने भाग लिया। टीबी जांच स्वास्थ्य शिविर के दौरान डिप्टी सीएमओ एवं जिला टीबी अधिकारी तरूण यादव ने जिला में 100 दिवसीय निक्षय अभियान की औपचारिक शुरूआत भी की। इस अभियान उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों में टीबी की शीघ्र पहचान कर उसके उन्मूलन के प्रयासों को गति देना है इस दौरान डिप्टी सीएमओ एवं जिला टीबी अधिकारी डॉ. तरुण यादव ने कहा कि बच्चों में टीबी की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करना स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि 100-दिवसीय निक्षय अभियान के माध्यम से जिले में विशेष रूप से पीडियाट्रिक टीबी पर फोकस करते हुए टीबी उन्मूलन के प्रयासों को और अधिक गति दी जाएगी।

डॉ. यादव ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों में लगातार खांसी, बुखार, वजन में कमी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच करवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ उठाएं। शिविर में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एन.के. मित्तल ने कहा कि बच्चों में टीबी की पहचान अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है, इसलिए समय पर जांच और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर न केवल रोग की शीघ्र पहचान में सहायक होते हैं, बल्कि अभिभावकों को सही मार्गदर्शन और विश्वास भी प्रदान करते हैं। डॉ. मित्तल ने कहा कि उनका निरंतर प्रयास रहेगा कि बच्चों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलें तथा टीबी जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। शिविर में बच्चों के लिए व्यापक एवं पूर्णत निशुल्क सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें बाल रोग परामर्श, टीबी स्क्रीनिंग, मुफ्त दवाइयां, एक्स-रे जांच और एचपीवी टीकाकरण शामिल रहे। लगभग 400 लाभार्थियों ने इस शिविर का लाभ उठाया। जांच के दौरान 70 छाती के एक्स-रे और 40 थूक के नमूनों की जांच मौके पर ही की गई, जिससे संभावित रोगियों की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित हो सका। स्वास्थ्य शिविर में सिविल अस्पताल के साथ-साथ मित्तल नर्सिंग होम, सीएचसी बढ़खालसा, पीएचसी कुंडली और शहरी डिस्पेंसरी कुंडली के स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सोनीपत अशोक भारद्वाज, कुण्डली नगर पालिका की चेयरपर्सन शिमला देवी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. नीरज यादव, सीएचसी बढ़खालसा की एसएमओ डॉ. चितवन, कुण्डली स्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र की एमओ डॉ. एचआर पासी, एमओ डॉ. चेतन, गन्नौर से बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. जेएस धनखड़, आईएपी की अध्यक्ष डॉ. बलदेव राज, आईएचपी के सचिव डॉ. निशांत मित्तल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

विकास का पिटारा खोलेगी गोहाना की धन्यवाद एवं विकास रैली-डॉ अरविंद शर्मा

गोहाना(सोनीपत)।

सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा है कि गोहाना की धन्यवाद और विकास रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव, शहर, समुदाय, हर वर्ग की भलाई के लिए विकास परियोजनाओं का पिटारा खोलेंगे। उन्होंने कहा कि रैली गोहाना में विकास की गाड़ी को तिगुना रफ्तार देते हुए गोहाना की सूरत बदलने का काम करेगी। रविवार को सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने गोहाना शहर में दर्जनभर स्थानों पर अलग, अलग समाज द्वारा आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए 29 मार्च को नई सब्जी मंडी, गोहाना में होने वाली विधानसभा धन्यवाद एवं विकास रैली का न्यौता दिया। बलराज नगर में डीएससी समाज द्वारा आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार गोहाना की जनता ने पहली बार भाजपा का कमल खिलाने की जिम्मेदारी निभाई है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इलाके में मूलभूत सुविधाओं को बढाने और विकास को तिगुनी रफ्तार देने के लिए पिटारा खोलकर सौगात देंगे। सभाओं में उमड़ रही भीड़ द्वारा भी कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा को भरोसा दिया गया कि गोहाना विधानसभा की धन्यवाद एवं विकास रैली में पूरे जोश, उत्साह के साथ पहुंचेंगे।

मानसी की कामयाबी से इलाके की बेटियों का बढ़ेगा सम्मान-डॉ अरविंद शर्मा

गोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बागड़ू में सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने यूपीएससी परीक्षा में 137वीं रैंक हासिल करने वाली बेटी मानसी डागर के सम्मान समारोह में शिरकत कर उसका अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानसी की यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और इससे अन्य बेटियों को भी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने मानसी के परिजनों व ग्रामीणों को भी इस सफलता पर बधाई दी।

-गोहाना इलाके में दर्जन भर स्थानों पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने दिया न्यौता

-कैबिनेट मंत्री ने यूपीएससी में कामयाब मानसी डागर को दिया आशीर्वाद

-बिचपडी में यज्ञ एवं भण्डारे में पहुंचकर विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

बिचपड़ी में यज्ञ-भंडारे में पहुंचे, विकास कार्यों का किया शुभारंभ

इसके बाद सहकारिता मंत्री गांव बिचपड़ी पहुंचे, जहां दुर्गा माता मंदिर परिसर में आयोजित यज्ञ एवं भंडारे में भाग लिया। उन्होंने संत-महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया गया। महंत बलबीर दास सहित पूरे गांव को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। उन्होंने पंचायत समिति, मुंडलाना की चेयरपर्सन सुशीला शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों से संवाद किया और विकास कार्यों पर चर्चा की।